सरगुजा परिवहन सर्विस

बनाम

स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, एम.पी. ग्वालियर एवं अन्य

12 नवंबर, 1986

[ई. एस. वेंकटरमैया और एम. एम. दत्त, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 21, 32, 226 और 227-रिट याचिका नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले ली गई- का प्रभाव- याचिकाकर्ता चाहे उसी विषय वस्तु के संबंध में कोई नई याचिका/मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया हो।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश XXIII, नियम 1- रिट याचिकाओं को वापस लेने के मामलों पर लागू होना।

सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम I, आदेश XXIII का उप-नियम (1) एक वादी को मुकदमा शुरू होने के बाद किसी भी समय सभी या किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ अपना मुकदमा छोड़ने की अनुमति देता है; उप-नियम (3) में कहा गया है कि जहां अदालत संतुष्ट है (ए) कि किसी औपचारिक दोष के कारण मुकदमा असफल होना चाहिए, या (बी) कि वादी को नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं मुकदमे

की विषय-वस्तु के आधार पर, यह उसे ऐसे मुकदमे से हटने की अनुमति दे सकता है, साथ ही नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता भी दे सकता है, जबकि उप-नियम (4) में प्रावधान है कि जहां वादी उप-नियम (1) के तहत किसी भी मुकदमे को छोड़ देता है या उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना वापस ले लेता है, उसे ऐसी विषय वस्तु के संबंध में कोई नया मुकदमा दायर करने से रोका जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, उसमें निर्धारित प्रक्रिया, जहाँ तक इसे लागू किया जा सकता है, रिट याचिकाओं के निपटारे में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है।

याचिकाकर्ता ने संविधान अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर अपनी पिछली रिट न्यायालय की अनुमति के बिना नई याचिका दायर करने के लिये, याचिका वापस ले ली। बाद में इसने पहली याचिका में दिए गए आदेश के खिलाफ एक और रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इसे यह कहते हुए सरसरी तौर पर खारिज कर दिया कि कोई भी दूसरी रिट याचिका उसी आदेश के खिलाफ नहीं है, जहां पिछली याचिका को नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ वापस नहीं लिया गया था।

विशेष अनुमति के लिए इस याचिका में यह तर्क दिया गया कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पिछली याचिका पर गुण-दोष के आधार पर

फैसला नहीं किया था, बल्कि याचिकाकर्ता को केवल इसे वापस लेने की अनुमति दी थी, इसे वापस लेने को बाद की रिट याचिका पर रोक नहीं माना जा सकता था।

इस सवाल पर: क्या एक याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय में उसके द्वारा दायर एक रिट याचिका वापस लेते हुये संस्थान की अनुमति के बिना इन अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालय में एक नई रिट याचिका दायर की जा सकती है, और क्या यह न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा यदि अंतर्निहित सिद्धांत नियम 1. संहिता का आदेश XXIII इन अनुच्छेदों के तहत रिट याचिकाओं के संबंध में सिविल प्रक्रिया अपनाई जाती है।

कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि उसी विषय के संबंध में उसके समक्ष नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि पिछली रिट याचिका नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले ली गई थी। [208 डी]

2.1 सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 1, आदेश XXIII में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जब एक वादी एक बार अदालत में मुकदमा दायर करता है और इस तरह कानून के तहत उसे दिए गए उपाय का लाभ उठाता है,

तो उसे के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पहले के मुकदमे को त्यागने के बाद या नए मुकदमे दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना उसे वापस लेने के बाद उसी विषय वस्तु को सार्वजनिक नीति के आधार पर न्याय के हित में रिट याचिका वापस लेने के मामलों में भी बढ़ाया जाना चाहिए। [206 डी,208 ए]

2.2 इनविटो बेनिफिसियम नॉन डेटूर- कानून किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या लाभ नहीं देता जिसकी वह इच्छा नहीं करता। जो कोई अधिकार छोड़ता है, त्यागता है या अस्वीकार करता है वह उसे खो देता है। [206 ई]

2.3 जहां एक याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय में उसके द्वारा दायर रिट याचिका वापस ले लेता है, नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना यह माना जाना चाहिए कि उसने रिट याचिका में भरोसा किए गए कार्रवाई के कारण के संबंध में इन अनुच्छेदों के तहत उपचार को छोड़ दिया है और नई याचिका दायर करने से रोक दिया गया है। [207 एच, 208 सी]

3.1 नियम 1 में सन्निहित सिद्धांत, संहिता का आदेश 233 सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह संहिता की धारा 11 में निहित पूर्वन्याय के नियम के समान नहीं है, जो ऐसे मामले पर लागू होता है जहां मुकदमा या मुद्दा पहले ही सुना जा चुका है और अंततः अदालत

द्वारा तय किया गया है। किसी मुकदमे के परित्याग या वापसी के मामले में, किसी मुकदमे का कोड्र पूर्व निर्णय नहीं होता है और न ही कोई मुददा शामिल होता है। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए वादी को उसी विषय वस्तु के संबंध में कोई नया मुकदमा दायर करने से रोका जाता है। [206 जी, एच.डी.2078]

3.2 इस तरह की वापसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के सवाल से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार के तहत मुकदमे या याचिका जैसे अन्य उपचारों पर रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि इस तरह की वापसी का कोई पूर्व न्याय मामला नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। [208 सी, 207 ई]

दरियाव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य. [1962] 1 एससीआर 575,- संदर्भित किया गया।

[किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी एक याचिका जिसमें याचिकाकर्ता बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करता है या संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करता है, पूरी तरह से एक अलग स्तर पर खड़ा है। यह प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है।] [208 ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 5665/1986

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विविध याचिका संख्या 188./ 1986 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.1.1986 से।

बी.पी. सिंह और रंजीत कुमार; याचिकाकर्ता की ओर से।

न्यायालय का आदेश वेंकटरमैया, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया। जनता ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत जारी जशपुरनगर-अंबिकापुर मार्ग पर स्टेज कैरिज चलाने के लिए परमिट की अवधि समाप्त होने पर, याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोगों ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर के समक्ष उक्त परमिट देने के लिए आवेदन दायर किया। जनता ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने भी अपने पक्ष में परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। जनता परिवहन सहकारी समिति द्वारा दायर नवीनीकरण के आवेदन को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह समय से बाधित था। अन्य आवेदकों की सापेक्ष योग्यताओं पर विचार करने पर, अर्थात् याचिकाकर्ता और अन्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के पक्ष में परमिट प्रदान किया। उक्त आदेश को मैसर्स अली अहमद एंड संस-प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा अपील में चुनौती दी गई थी, जो कि राज्य परिवहन अपीलीय

न्यायाधिकरण के समक्ष भी उक्त परमिट के लिए एक आवेदक था। अन्य असफल आवेदकों ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुदान पर सवाल उठाते हुए अलग-अलग अपील दायर कीं। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 19.9.1985 ने याचिकाकर्ता के पक्ष में परमिट देने के आदेश को दो आधारों पर रद्द कर दिया, अर्थात् याचिकाकर्ता कंपनी के मालिक मो. जाहिद खान एक प्रैक्टिसिंग वकील थे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में परिवहन व्यवसाय करना बंद कर दिया था और मेसर्स अली अहमद एंड संस. के पक्ष में परमिट दे दिया था। न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने फाइल पर एक रिट याचिका संख्या 2945/1985 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दायर की, उस याचिका को 4.10.1985 को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था। उस दिन उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

> "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री वाई.एस. धर्माधिकारी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति है। याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।"

बाद में याचिकाकर्ता ने फिर से मप्र उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका संख्या 188/1985 दायर की। वह याचिका 17 जनवरी 1985 को सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के समापन पर उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"याचिकाकर्ता के लिए श्री पी.आर. भावे ने प्रवेश पर सुनवाई की। यह रिट याचिका राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुदान को रद्द करने और इसके बदले प्रतिवादी क्रमांक 3 को परमिट देने के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। याचिकाकर्ता ने पहले आक्षेपित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका क्रमांक एम.पी. 2945/85 दायर की थी, जिसे 4.10.1985 को वापस ले लिया गया। उसी आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी रिट याचिका अनुमत नहीं है। नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ पिछली याचिका वापस नहीं ली गई। इसके अलावा, हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती. अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 3 को अनुमति दे दी है क्योंकि उसे याचिकाकर्ता से बेहतर पाया गया है। इसके अलावा, वह एक प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते परिवहन व्यवसाय नहीं कर सकता था। अन्य ऑपरेटरों की ऐसी ही याचिका यह अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।

तदनुसार, याचिका को सरसरी तौर पर खारिज किया जाता है।"

प्रवेश के चरण में रिट याचिका को खारिज करने के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें अदालत से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष मुख्य तर्क यह दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका को खारिज करने में गलती की थी, जिससे यह मामला उत्पन्न हुआ था, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने पिछली रिट याचिका वापस ले ली थी, जिसमें उन्होंने नई याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना 4.10.1985 को नयायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया था। विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पिछली याचिका पर गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं किया था, बल्कि केवल याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी, इसलिए उक्त पिछली याचिका को वापस लेने को बाद की रिट याचिका पर रोक नहीं माना जा सकता था।

इस मामले में हमें नई याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत

दायर रिट याचिका को वापस लेने के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि जहां तक इसे लागू किया जा सकता है वहां निर्धारित प्रक्रिया रिट याचिकाओं के निपटारे में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है। संहिता के आदेश XXIII का नियम 1 मुकदमे की वापसी और ऐसी वापसी के परिणामों का प्रावधान करता है। 1976 के अधिनियम 104 द्वारा इसके संशोधन से पहले, संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 में एक मुकदमे की दो प्रकार की वापसी का प्रावधान था। अर्थात्, (i) पूर्ण वापसी, और (ii) कार्रवाई के समान कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति से वापसी। वापसी की पहली श्रेणी उसके उप-नियम (1) द्वारा शासित होती थी, जैसा कि उस समय था, जिसमें प्रावधान था कि किसी मुकदमे की स्थापना के बाद किसी भी समय वादी, सभी या किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ 'वापस ले सकता है' उसका मुकदमा या उसके दावे का एक हिस्सा छोड़ देना। दूसरी श्रेणी उसके उप-नियम (2) द्वारा शासित होती थी, जिसमें प्रावधान था कि जहां न्यायालय संतुष्ट था (ए) कि कुछ औपचारिक दोष के कारण मुकदमा विफल हो जाना चाहिए या (बी) कि वादी को किसी मुकदमे की विषय-वस्तु या दावे के हिस्से के लिए एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार थे, यह ऐसी शर्तों पर हो सकता है जैसा वह उचित समझे। वादी को ऐसे मुकदमे से

हटने या दावे के एक हिस्से को छोड़ने की अनुमति दें, साथ ही ऐसे मुकदमे की विषय-वस्तु या दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दें। संहिता के आदेश XXIII के पूर्व नियम I के उप-नियम (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां वादी किसी मुकदमे से पीछे हट गया या उप नियम (2) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना दावे का एक हिस्सा छोड़ दिया, वह अदालत द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक खर्च के लिए उत्तरदायी होगा और उसे ऐसी विषय-वस्तु या दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में कोई नया मुकदमा दायर करने से रोका जाएगा। चूँकि यह माना गया कि निकासी की दोनों श्रेणियों के संबंध में 'वापसी' शब्द के उपयोग से भ्रम पैदा हुआ, इस तरह के भ्रम से बचने के लिए नियम में संशोधन किया गया। संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 का प्रासंगिक भाग अब इस प्रकार है:-

> "नियम 1. मुक़दमे को वापस लेना या दावे के एक हिस्से का परित्याग-(1) मुक़दमे की स्थापना के बाद किसी भी समय, वादी सभी या किसी प्रतिवादी के विरुद्ध अपना मुक़दमा छोड़ सकता है या अपने दावे का एक हिस्सा छोड़ सकता है:
>
> (3) जहां न्यायालय संतुष्ट है-

(ए) कि कोई मुकदमा किसी औपचारिक दोष के कारण विफल हो जाना चाहिए, या

(बी) किसी मुकदमे की विषय-वस्तु या दावे के भाग के लिए वादी को नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं,

यह, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, वादी को ऐसे मुकदमे या दावे के ऐसे हिस्से से हटने की अनुमति दे सकता है, साथ ही ऐसे मुकदमे की विषय-वस्तु या दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता भी दे सकता है।

(4) जहां वादी-

(ए) उप-नियम एफ के तहत किसी भी मुकदमे या दावे के हिस्से को छोड़ देता है

(1), या

(बी) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना किसी मुकदमे या दावे के हिस्से से हट जाता है,

वह ऐसी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा जो न्यायालय दे सकता है और उसे ऐसी विषय-वस्तु या दावे के ऐसे हिस्से

के संबंध में कोई नया मुकदमा दायर करने से रोका जाएगा।"

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जबकि संहिता के आदेश XXIII के पूर्व नियम I के उप-नियम (1) में 'उसका मुकदमा वापस लें' शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, आदेश XXIII के नए नियम 1 के उप-नियम (1) में संहिता में 'उसका मुकदमा छोड़ो' शब्दों का प्रयोग किया गया है। नया उपनियम (1) केस पर लागू होता है जहां न्यायालय किसी मुकदमे या दावे के ऐसे हिस्से से पीछे हटने की अनुमति नहीं देता है, ऐसे मुकदमे की विषय-वस्तु या दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ। नए उप-नियम (3) में, जो पूर्व उप-नियम (2) से मेल खाता है, व्यावहारिक रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है और उस उप-नियम के तहत न्यायालय को उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन किसी मुकदमें से निकासी की अनुमति देने का अधिकार है, ऐसे मुकदमे की विषय-वस्तु के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ। संहिता के आदेश XXIII के नए नियम 1 के उप-नियम (4) में प्रावधान है कि जहां वादी उप-नियम (1) के तहत किसी मुकदमे या दावे के हिस्से को छोड़ देता है या उप-नियम (3) में संदर्भित अनुमति के बिना किसी मुकदमे या दावे के हिस्से से हट जाता है, वह ऐसी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा जो न्यायालय दे सकता है और उसे ऐसी विषय-वस्तु या

दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में कोई नया मुकदमा दायर करने से भी रोका जाएगा।

इस प्रकार वर्तमान संहिता किसी मुकदमे को 'त्याग' करने और नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमे को 'वापस लेने' के बीच अंतर करती है। इसमें प्रावधान है कि जहां वादी संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना मुकदमा छोड़ देता है या मुकदमे से हट जाता है, तो उसे ऐसे संबंध में कोई नया मुकदमा ऐसी विषय-वस्तु या दावे का ऐसा भाग दायर करने से रोक दिया जाएगा। संहिता के आदेश XXIII के नियम I में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जब एक वादी एक बार अदालत में मुकदमा दायर करता है और इस तरह कानून के तहत उसे दिए गए उपाय का लाभ उठाता है, तो उसे उसी विषय के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पहले के मुकदमे को त्यागने के बाद या उसे वापस लेकर न्यायालय की अनुमति के बिना नया मुकदमा दायर करने के लिए। इनविटो बेनिफिसियम नॉन डेटूर- कानून किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या लाभ नहीं देता जिसकी वह इच्छा नहीं करता। जो कोई किसी अधिकार को छोड़ देगा, छोड़ देगा या तिरस्कार करेगा, वह उसे खो देगा। किसी वादी को बिना किसी उचित कारण के एक ही कारण पर बार-बार मुकदमा दायर करके अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए, संहिता इस बात पर जोर देती है कि उसे इनमें से किसी एक को स्थापित करने के

बाद नया मुकदमा दायर करने के लिए आदेश XXIII के नियम 1 के उप-नियम (3) में उल्लिखित दो आधार पर अदालत की अनुमति लेनी चाहिए। उपरोक्त नियम में अंतर्निहित सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित है, लेकिन यह संहिता की धारा 11 में निहित न्यायिक निर्णय के नियम के समान नहीं है, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी अदालत किसी भी मुकदमे या मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी जिसमें मामला सीधे या पर्याप्त रूप से शामिल हो। एक ही पक्ष के बीच, या उन पक्षकारो के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई दावा करता है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा करते हुए, ऐसे बाद के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय में, यह मुद्दा सीधे या पर्याप्त रूप से विवाद में रहा है। वह मुकदमा जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है, और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंततः निर्णय लिया गया है। पूर्व न्याय का नियम उस मामले पर लागू होता है जहां मुकदमे या मुद्दे की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और अंततः न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। नया मुकदमा दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमा छोड़ने या वापस लेने के मामले में, मुकदमे का कोई पूर्व निर्णय नहीं होता है या कोई मुद्दा शामिल होता है, फिर भी संहिता प्रदान करती है, जैसा कि पहले कहा गया है, कि दूसरा मुकदमा दायर किया जाएगा। जब न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना

पहला मुकदमा वापस ले लिया जाता है, तो यह संहिता के आदेश XXIII के नियम I के उप-नियम (4) में नहीं आता है।

हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर रिट याचिकाओं के संबंध में संहिता के आदेश XXIII के नियम I के अंतर्निहित सिद्धांत को अपनाया जाता है तो क्या यह न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा या नहीं। यह सामान्य ज्ञान है कि अक्सर रिट याचिका पर कुछ समय तक सुनवाई के बाद जब याचिकाकर्ता या उसके वकील को पता चलता है कि न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करने का आदेश पारित करने की संभावना नहीं है, तो याचिकाकर्ता या उसके वकील द्वारा अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है। याचिकाकर्ता को नई रिट याचिका दायर करने की अनुमति के बिना रिट याचिका से हटना होगा। एक अदालत जो याचिका को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह आम तौर पर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता नहीं देगी, जबकि वह याचिका को वापस लेने की अनुमति देने के लिए सहमत हो सकती है। यह स्पष्ट है कि जब एक बार उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं वापस ले ली जाती है तो उसे रिट याचिका में पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसे उच्च न्यायालय द्वारापारित आदेश से पीड़ित पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है। जैसा कि दरियाओ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1962] 2 एस.सी.आर. 575 में

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के प्रश्न से जुड़े मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करें क्योंकि ऐसे मामले में उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। दरियाओ के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणी पृष्ठ 593 पर पाई जाती है और यह इस प्रकार है:

> "यदि याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी जाती है तो यह अनुच्छेद 32 के तहत अगली याचिका पर रोक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार जो निष्कर्ष निकले हैं हमारे द्वारा केवल न्यायिक मुद्दे तक ही सीमित रखा गया है, जिसे इन रिट याचिकाओं में प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तर्क दिया गया है और किसी अन्य मुद्दे के रूप में नहीं।"

विचारणीय बात यह है कि क्या याचिकाकर्ता भारत के संविधानके अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में उसके द्वारा दायर एक रिट याचिका वापस लेते हुये संस्थान की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय में उस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नई रिट याचिका दायर कर सकता है। इस बिंदु पर दरियाव के मामले (उपरोक्त) में निर्णय से कोई सहायता नहीं

मिलती है। लेकिन हमारा विचार है कि संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 में अंतर्निहित सिद्धांत को न्याय प्रशासन के हित में रिट याचिका वापस लेने के मामलों में भी बढ़ाया जाना चाहिए। न्यायिक आधार पर नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति के आधार पर जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह वादी को बेंच-हंटिंग रणनीति में शामिल होने से भी हतोत्साहित करेगा। किसी भी स्थिति में ऐसे मामले में याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को एक बार फिर से लागू करने की अनुमति देने का कोई उचित कारण नहीं है। जबकि नई रिट याचिका दायर करने की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को वापस लेने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमे या याचिका जैसे अन्य उपचारों पर रोक नहीं लग सकती है क्योंकि इस तरह की वापसी न्यायिक अधिकार के दायरे में नहीं आती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार को याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में भरोसा किए गए कार्रवाई के कारण के संबंध में त्याग दिया गया माना जाना चाहिए, जब वह ऐसी अनुमति के बिना इसे वापस ले लेता है। मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि उसी विषय-वस्तु के संबंध में उसके समक्ष एक नई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि पिछली रिट याचिका को नई याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ले लिया गया था। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस आदेश में जो कुछ भी कहा है उसे किसी व्यक्ति की

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी रिट याचिका पर लागू नहीं माना जा सकता है जिसमें याचिकाकर्ता रिट की प्रकृति के मुद्दे के लिए प्रार्थना करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार को लागू करने का प्रयास करता है क्योंकि ऐसा मामला पूरी तरह से एक अलग स्तर पर खड़ा होता है। हम, हालाँकि इस प्रश्न को खुला छोड़ते है।

गुण-दोष के आधार पर भी हमें उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का कोई आधार नहीं मिलता। परिणामस्वरूप हम विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हैं।

पी.एस.एस.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।